डिजिटल संस्करण
केशव टाइम्स
13 फरवरी 2026
शुक्रवार

ब्रह्मपुर में कानून-व्यवस्था पर एसपी सख्त : 200 लंबित कांडों पर लगाई फटकार, नशा-जुआ और अतिक्रमण पर विशेष

2

एक नजर

रेरा को बंद ही कर दो, सिर्फ बिल्डरों का देता है साथ

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि समय आ गया है कि सभी प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) के गठन पर पुनर्विचार करें क्योंकि यह संस्था डिफाल्ट करने वाले बिल्डरों की मदद करने के अलावा कुछ नहीं कर रही। अदालत ने कहा कि रेरा को जिन लोगों के लिए बनाया गया था, वे पूरी तरह से उदास, निराश और हताश हैं। बेहतर होगा कि इस संस्था को समाप्त कर दिया जाए, इस अदालत को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी।प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने ये टिप्पणियां हिमाचल प्रदेश सरकार को रेरा का कार्यालय अपनी पसंद की जगह पर स्थानांतरित करने की अनुमति देते हुए कीं। पीठ ने हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य लोगों की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें प्रदेश के रेरा कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने से जुड़े मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।

ब्राजिल के राष्ट्रपति लूला का भारत दौरा

नई दिल्ली। अगले सप्ताह राजधानी दिल्ली में कूटनीतिक गतिविधियां चरम पर रहने वाली हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के प्रस्तावित दौरे के साथ ही अब ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा भी 18 से 22 फरवरी 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रहे इस दौरे को भारत-ब्राजील रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। राष्ट्रपति लूला 19-20 फरवरी को आयोजित दूसरे 'एआई इम्पैक्ट समिट' में हिस्सा लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी इस सम्मेलन में प्रमुख मेहमान के तौर पर शामिल होंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा 21 फरवरी को उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें दोनों देश आपसी संबंधों की पूरी रूपरेखा की समीक्षा करेंगे। इस दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, नवीकरणीय ऊर्जा, दुर्लभ खनिजों, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष सहयोग जैसे क्षेत्रों में प्रगति पर चर्चा होगी।

3.60 लाख करोड़ की डिफेंस डील को मंजूरी, 114 राफेल जेट्स खरीदेगा भारत

- नए राफेल जेट्स की खरीद को मोदी सरकार की तरफ से इजाजत मिल गई
- देश की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया

एजेंसी। नई दिल्ली

भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा होने जा रहा है। और इसके लिए मोदी सरकार ने फ्रांस से नए राफेल जेट्स की खरीद को मंजूरी दे दी है। पूरी दुनिया ने पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फाइटर जेट राफेल का दम देखा था कि कैसे भारत ने पाकिस्तान पर एयर डॉमिनेंस बनाए रखा था। और पलक झपकते ही पाकिस्तान का नूर खान समेत तमाम एयरबेस पर अटैक किया था। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में नए राफेल जेट्स की खरीद को मंजूरी दी गई है। देश की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई एक बड़ी बैठक में 3.60 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस डील को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले का सबसे बड़ा मकसद दुश्मन देशों की चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना और भारतीय सेना को दुनिया की सबसे आधुनिक सेना बनाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में भारत ने 3.60 लाख करोड़ की मेगा डिफेंस डील को मंजूरी दी है। इस ऐतिहासिक फैसले के तहत 114 फाइटर जेट्स और खतरनाक मिसाइलों समेत कई घातक हथियार खरीदे जाएंगे, जिससे सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इस मेगा डील में सबसे बड़ी खबर भारतीय वायुसेना के लिए है. अब वायुसेना के बेड़े में 114 नए फाइटर जेट्स (राफेल जैसे विमान) शामिल करने का रास्ता साफ हो गया है। खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर विमान भारत में ही बनाए जाएंगे, जिससे देश के अंदर ही रोजगार के नए मौके भी बढ़ेंगे। साथ ही, आसमान से जासूसी करने वाले नए सैटेलाइट सिस्टम को भी मंजूरी मिली है।

दुश्मन की पनडुब्बियों पर रहेगी पैनी नजर

समंदर में भारत की ताकत बढ़ाने के लिए नौसेना को पी 81 निगरानी विमान मिलेंगे। ये विमान पानी के नीचे छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों को आसानी से पहचान लेते हैं। इसके अलावा, युद्धपोतों के लिए बिजली बनाने वाली मशीनें (जनरेटर) भी अब भारत में ही तैयार की जाएंगी, ताकि हमें दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े। इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर की स्वदेशी खरीद से हमारी विदेशी निमार्ताओं पर निर्भरता घटेगी और नेवी की बिजली उत्पादन जरूरतों में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होगी।

थलसेना और टैंकों का कायाकल्प

जमीनी लड़ाई में हमारी सेना और ताकतवर हो, इसके लिए पुराने टैंकों को नई तकनीक से अपडेट किया जाएगा। साथ ही, दुश्मन के टैंकों को उड़ाने के लिए स्वदेशी विभव माइन्स खरीदी जाएंगी। इससे बॉर्डर पर तैनात हमारे सैनिकों की सुरक्षा और बढ़ जाएगी। समुद्र तटों की रखवाली करने वाले कोस्ट गार्ड के विमानों को अब आधुनिक कैमरों और सेंसर से लैस किया जाएगा. सरकार ने सरकारी कंपनी एचसीएल से 8 नए डोर्नियर विमान खरीदने का भी फैसला लिया है, जिसकी कुल कीमत करीब 2,312 करोड़ रुपये है।

राहुल गांधी ने अमेरिकी ट्रेड डील को किसान विरोधी बताया

एफआईआर करो या सदस्यता लो, मैं नहीं डरूंगा', ट्रेड डील पर : राहुल गांधी

- आरोप लगाया कि डील से देश की खाद्य सुरक्षा कमजोर होगी
- किसानों के लिए संसद से सड़क तक लड़ने का संकल्प दोहराया

एजेंसी। नई दिल्ली

संसद में अमेरिका से हुए ट्रेड डील को लेकर गंभीर सवाल उठाने के बाद सरकार और भाजपा की ओर से अपने उपर हो रहे भारी चौतरफा हमलों के बावजूद लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस डील में किसानों और देश के हितों की बलि चढ़ाए जाने के अपने आरोपों को दुहराया है। लोकसभा की उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए भाजपा सदस्य की ओर से दिए गए प्रस्ताव के बाद गुरूवार को राहुल गांधी ने सत्तापक्ष को जवाबी चुनौती देते हुए कहा चाहे उन्हें गाली दी जाए, एफआईआर हो, विशेषाधिकार हनना प्रस्ताव लाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि संसद में ट्रेड डील पर उन्होंने सच्चाई बोली है। भाजपा और सरकार को चाहे यह सच्चाई अच्छी न लगे और उनके खिलाफ जो कुछ भी करना है वह कर ले मगर वे अपनी बातों से एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। सरकार के मंत्रियों-भाजपा नेताओं के सियासी हमलों के बाद गुरूवार शाम राहुल गांधी ने कहा कि जो ट्रेड डील किसानों की रोजी-रोटी छीने, देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे वह किसान-विरोधी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ वे तथा उनकी पार्टी अन्नदाताओं के हितों से किसान विरोधी मोदी सरकार को समझौता नहीं करने देंगे। नेता विपक्ष ने सवाल उठाया कि आखिर सरकार हमेशा किसानों की कुबार्नी देने के लिए क्यों तैयार रहती है।

डील से देश की खाद्य सुरक्षा कमजोर होगी

प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए नेता विपक्ष ने कहा कि पहले अपने अरबपति मित्रों के मुनाफे के लिए काले कानून लाए थे, अब अपने गले से अमेरिकी शिकंजा हटाने के लिए ट्रंप के अमेरिका के लिए भारतीय खेती के दरवाजे खोल दिए हैं और कल इन्हीं सब मित्रों के लिए यही दरवाजे और भी चौड़े किए जाएंगे। समझौते पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस डील में अमेरिकी कृषि उत्पादों पर नॉन टैरिफ बैरियर' हटाने की बात की गई है और यह विदेशी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार का खोलना है जो भारत की खाद्य सुरक्षा और किसानों की रोझी-रोटी पर सीधा हमला है। कपास, सोयाबीन, ज्वार, फल और ड्राय फ्रूट्स के किसान पहले ही खतरे में आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत के 99.5 प्रतिशत किसान छोटे और गरीब हैं। उनके पास न पर्याप्त सहायता है, न सब्सिडी, पूरा जोखिम किसान उठाता है। जबकि अमेरिका में खेती बड़े पैमाने पर मशीनों से होती है जिस पर वहां की सरकार भारी सब्सिडी देती है।

संसद से सड़क तक लड़ने का संकल्प दोहराया

राहुल गांधी ने कहा कि सस्ती सब्सिडी वाली अमेरिकी खेती से मुकाबला करने को मजबूर किया गया तो भारतीय किसान उनके सामने टिक नहीं पाएगा और भारत के किसानों को बबार्दी झेलनी पड़ेगी। इस समझौते में किसानों से सलाह नहीं लेने तथा संसद को पूरी जानकारी नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात करने वालों ने उल्टा अब किसानों के भविष्य को ही दांव पर लगा दिया है। ऐसे में देश के अन्नदाताओं की लड़ाई वे संसद से सड़क तक ही नहीं हर मंच से लड़ेंगे ताकि देश की खाद्य सुरक्षा की रक्षा की जा सके।

भारत बंद के समर्थन में राहुल गांधी

एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साझा मंच के आह्वान पर आज गुरुवार को देशव्यापी हड़ताल रही। पूरे देश में बिजली, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, स्वास्थ्य के साथ-साथ गैस और पानी आपूर्ति से जुड़ी सेवाओं पर असर देखने को मिला। इस आम हड़ताल में अलग-अलग क्षेत्र के 30 करोड़ कामगार शामिल हुए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी इस बंद को समर्थन प्राप्त था, लेकिन वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इसका विरोध किया। शशि थरूर ने कहा कि भारत बंद असल में सिर्फ एक और केरल बंद है। जहां बाकी भारत ऐसे जबरदस्ती के विरोध से आगे बढ़ चुका है, वहीं केरल आज भी खास तौर पर अल्पसंख्यकों के असंगठित बहुमत पर इस संगठित अत्याचार का बंधक बना हुआ है।" कांग्रेस सांसद ने कहा कि जब से मैं राजनीति में आया हूं, मेरा स्टैंड एक जैसा रहा है: मैं विरोध करने के अधिकार का समर्थन करता हूं, लेकिन रुकावट डालने के अधिकार का नहीं। किसी भी भारतीय को किसी दूसरे के आजाद आने-जाने में रुकावट डालने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। शशि थरूर ने कहा, "हमने अपने मिलिटेंट यूनियनवाद से इंडस्ट्री को दूर भगा दिया है; अब, "मसल पावर" के इन पुराने तरीकों से चिपके रहकर, जो नागरिकों को जबरदस्ती उनके अपने घरों में कैदी की तरह कैद करते हैं, और दुकानदारों को अपनी दुकानें बंद करने के लिए मजबूर करते हैं, हम यह पक्का कर रहे हैं कि हमारा राज्य युवाओं और बिजनेस के लिए अच्छा न रहे। अब समय आ गया है कि हम इस खुद को नुकसान पहुंचाने वाली आदत से बाहर निकलें। हम इसे हमेशा कंस्ट्रक्टिव असहमति से बदल सकते हैं।

अब परेशान नहीं कर पाएंगे रिकवरी एजेंट आरबीआई ने लागू किए सख्त नियम

एजेंसी। नई दिल्ली

आरबीआई की तरफ से संचालित देश के जितने भी वित्तीय संस्थान (बैंक, ग्रामीण बैंक, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, सहकारी बैंक आदि) की तरफ से नामित रिकवरी एजेंट अब किसी भी सूरत में कर्ज चुकाने में असमर्थ रहने वाले या देरी करने वाले ग्राहकों से बदतमीजी से पेश नहीं आएंगे। आरबीआई ने गुरुवार को इस बारे में विस्तृत लोन रिकवरी और रिकवरी एजेंट्स की नियुक्ति को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोन चुकाने में असमर्थ या देरी करने वाले ग्राहकों को अनुचित दबाव से बचाना। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंकों को अब एक स्पष्ट नीति बनानी होगी, जिसमें रिकवरी एजेंट्स की योग्यता, जांच, आचार संहिता और निगरानी शामिल हो। इससे विशेष रूप से वैसे लोगों को राहत मिलेगी जो रिकवरी के दौरान उत्पीड़न का शिकार होते हैं। अब बैंकों को सुनिश्चित करना होगा कि रिकवरी प्रक्रिया न केवल कानूनी हो, बल्कि मानवीय भी।पिछले कई वर्षों से रिकवरी एजेंट्स के गैर-कानूनी और अमानवीय व्यवहार की शिकायतें लगातार बढ़ रही थीं। कई मामलों में एजेंट्स ने ग्राहकों को धमकी दी, अपशब्द कहे, परिवार को परेशान किया या यहां तक कि शारीरिक हिंसा की धमकी दी। कुछ रिपोर्ट्स में तो ऐसे मामले सामने आए जहां रिकवरी के दबाव में ग्राहकों ने आत्महत्या तक कर ली। उदाहरण के लिए 2023-2024 में कई राज्यों से ऐसी खबरें आईं जहां माइक्रोफाइनेंस लोन के रिकवरी एजेंट्स ने महिलाओं और किसानों को इतना तंग किया कि वे चरम कदम उठाने पर मजबूर हो गए। सबसे पहले, बैंकों को रिकवरी एजेंट्स की नियुक्ति से पहले उनकी योग्यता और पृष्ठभूमि की जांच करनी होगी।

राजस्थान माइंस हादसा : छठे दिन गहरे पानी में उतरे गोताखोर, जारी किया वीडियो

- **जूता मिलने के बाद बढ़ी अनहोनी की आशंका, छह दिन बाद भी जनप्रतिनिधियों की चुप्पी से आहत परिजन**

केटी न्यूज/डुमरांव

राजस्थान के अरवल जिले स्थित उड़ेला माइंस क्षेत्र में पहाड़ तोड़ने के दौरान हुए भीषण हादसे में लापता डुमरांव थाना क्षेत्र के रजडीहा गांव निवासी रामानंद तिवारी की तलाश छठे दिन भी जारी रही। राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाते हुए गोताखोरों की टीम को सैकड़ों फीट गहरे पानी में उतारा गया। गोताखोरों द्वारा पानी के भीतर की स्थिति का एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर खाई में समा गया है। भारी चट्टानों और मलबे के कारण तलाश अभियान अब भी बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। ज्ञात हो कि शुक्रवार की शाम माइंस में पहाड़ का बड़ा हिस्सा अचानक ढह गया था। उस

समय पोकलेन मशीन चला रहे रामानंद तिवारी मशीन सहित सैकड़ों फीट गहरी पानी भरी खाई में गिर गए थे। प्रशासन ने चौथे दिन मशीन को बाहर निकाल लिया था, लेकिन चालक का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। पांचवें दिन खाई के किनारे से रामानंद का एक जूता बरामद हुआ था, जिसने परिजनों की चिंता और बढ़ा दी थी।

छठे दिन गोताखोरों द्वारा जारी वीडियो ने हादसे की भयावहता को और स्पष्ट कर दिया है। पानी के भीतर बड़े-बड़े पत्थरों और मलबे का ढेर दिखाई दे रहा है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि युवक तक पहुंचना आसान नहीं है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि हर संभव प्रयास जारी है और खोज अभियान को रोका नहीं जाएगा।

इधर, रजडीहा गांव स्थित रामानंद के घर में मातम का माहौल और गहरा हो गया है। पिता पारसनाथ तिवारी, माता सीता देवी तथा बहन शिल्पी का रो-रोकर बुरा हाल है। पांचवें दिन जूता मिलने के बाद से ही परिवार के मन में अनहोनी की आशंका घर करने लगी है। जैसे-जैसे दिन बीतते जा रहे हैं और कोई ठोस सूचना नहीं मिल रही, वैसे-वैसे परिवार के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। छठे दिन भी घर में चूल्हा नहीं जला। पूरे गांव में शोक और चिंता का वातावरण बना हुआ है।

परिवार को इस बात का भी गहरा दुख है कि घटना के छह दिन गुजर जाने के बावजूद कई स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अब तक उनकी सुध नहीं ली है। परिजनों का कहना है कि यदि जनप्रतिनिधि सक्रिय पहल करें तो प्रशासनिक स्तर पर और दबाव बन सकता है तथा खोज अभियान को और गति मिल सकती है। गांव के लोग ईश्वर से रामानंद की सलामती की प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से उम्मीद की जा रही है कि वे संवेदनशीलता दिखाते हुए हर संभव कदम उठाएं, ताकि लापता युवक का जल्द से जल्द पता चल सके। छठे दिन भी उम्मीद और आशंका के बीच झूलता परिवार अपने बेटे की एक झलक पाने की आस लगाए बैठा है।

जनता दरबार में उठे धार्मिक संवेदनशीलता, अवैध कारोबार व मंदिर के समीप मांस बिक्री का उठा मुद्दा

ब्रह्मपुर में कानून-व्यवस्था पर एसपी सख्त : 200 लंबित कांडों पर लगाई फटकार, नशा-जुआ और अतिक्रमण

- **महाशिवरात्रि को लेकर सुरक्षा का कड़ा खाका तैयार**

केटी न्यूज/ब्रह्मपुर

ब्रह्मपुर थाना परिसर में गुरुवार को एसपी ने जनता दरबार का आयोजन कर आम जनता की समस्याओं को सुना तथा उसके त्वरित निष्पादन की दिशा में सख्ती से निर्देश दिए। एसपी का यह जनता दरबार महज शिकायतों की औपचारिक सुनवाई नहीं रहा, बल्कि यह स्थानीय कानून-व्यवस्था की परतें खोलने वाला मंच साबित हुआ। एसपी शुभम आर्य की अध्यक्षता में हुए इस दरबार में जहां एक ओर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे, वहीं दूसरी ओर बढ़ते नशा, जुआ और अवैध गतिविधियों को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आईं। एसडीपीओ पोलस्त कुमार भी मौजूद रहे। जनता दरबार में अपेक्षित भीड़ नहीं जुटने पर एसपी ने नाराजगी जताई और स्पष्ट कहा कि आमजन की समस्याएं सुनने के लिए बनाए गए इस मंच का व्यापक प्रचार-प्रसार

अनिवार्य है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भविष्य में इसकी समुचित सूचना गांव-गांव तक पहुंचाने का निर्देश दिया।

दरबार में सबसे तीखा मुद्दा ब्रह्मपुर गौ रक्षा दल के प्रतिनिधियों ने उठाया। उन्होंने ऐतिहासिक बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर परिसर के समीप खुले में मांस बिक्री पर आपत्ति जताते हुए इसे धार्मिक आस्था से जुड़ा संवेदनशील विषय बताया। उनका कहना था कि मंदिर क्षेत्र की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रशासन को स्पष्ट और ठोस कदम उठाने चाहिए। इस पर एसपी ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

इसी बीच स्थानीय महिला तेरगनी देवी ने अपने साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस की निष्क्रियता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को निष्पक्ष जांच कर शीघ्र कार्रवाई का निर्देश दिया। अतिक्रमण और धमकी का मामला भी दरबार में गूंजा। रघुनाथपुर की मीरा देवी ने आरोप लगाया कि उनके घर के सामने ईंट रखकर अस्थायी कब्जा किया गया है। विरोध करने पर मारपीट और एससी-एसटी एक्ट में फंसाने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए न्याय की गुहार लगाई। एसपी ने भूमि विवाद से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और त्वरित जांच का निर्देश दिया।

जनता दरबार का सबसे गंभीर पहलू क्षेत्र में बढ़ती अवैध गतिविधियों को लेकर सामने आया। रघुनाथपुर के पैक्स अध्यक्ष सह पूर्व प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि जगनारायण चौधरी ने आरोप लगाया कि इलाका शराब और हीरोइन की बिक्री का अड्डा बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी नशे और जुआ के दलदल में फंसकर अपना भविष्य बर्बाद कर रही है। इस पर एसपी ने विशेष अभियान चलाने का संकेत देते हुए कहा कि अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

जनता दरबार के दौरान एसपी ने ब्रह्मपुर थाने में लंबित लगभग 200 कांडों की समीक्षा की। उन्होंने अनुसंधानकर्ताओं की कड़ी क्लास लगाते हुए स्पष्ट कहा कि लंबित मामलों की संख्या चिंताजनक है और जांच में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया।

आगामी 15 फरवरी को बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर में आयोजित महाशिवरात्रि को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखा। एसपी ने बताया कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, बैरिकेडिंग, यातायात नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन की विशेष व्यवस्था की जा रही है।

महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मियों की अलग-अलग तैनाती होगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। संवेदनशील स्थलों पर विशेष नजर रखी जाएगी और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रहेगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्गों का उपयोग करने और दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

एसपी शुभम आर्य ने स्पष्ट संदेश दिया कि कानून-व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा। जनता दरबार में उठे मुद्दों ने यह साफ कर दिया कि क्षेत्र में प्रशासनिक सक्रियता की आवश्यकता है। अब देखना यह है कि दिए गए निर्देश जमीन पर कितनी तेजी से लागू होते हैं और आमजन को राहत कब तक मिलती है।

एक नजर

सघन जांच अभियान से मचा हड़कंप नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई

कृष्णाब्रह्म। सड़क सुरक्षा को लेकर कृष्णाब्रह्म थाना पुलिस गुरुवार को पूरी तरह सक्रिय दिखी। टुड़ीगंज-खेवली मार्ग पर चलाए गए सघन वाहन जांच अभियान के दौरान नियमों की अनदेखी करने वाले चालकों पर कार्रवाई की गई। जांच के क्रम में ट्रक, चार पहिया और दोपहिया सहित कुल नौ वाहनों को पकड़ा गया। इन सभी वाहनों पर यातायात नियमों के उल्लंघन के आरोप में कुल 12 हजार रुपये का जुमार्ना लगाया गया। अचानक शुरू हुई जांच से वाहन चालकों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। कई बाइक सवार दूर से ही पुलिस को देखकर रास्ता बदलते नजर आए। बिना कागजात, हेलमेट या अन्य आवश्यक दस्तावेजों के वाहन चला रहे लोगों में विशेष रूप से हड़कंप मचा रहा। थानाध्यक्ष रवि कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

अग्नि सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन का जागरूकता अभियान शुरू, नुक्कड़ नाटक टीम रवाना

बक्सर। जिले में अग्नि सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने विशेष जन जागरूकता अभियान की शुरूआत की है। इस अभियान के माध्यम से आम लोगों को आग से बचाव और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के प्रति जागरूक किया जाएगा। गुरुवार को जिलाधिकारी साहिला ने गृहरक्षक सह जिला अग्निशमन कार्यालय परिसर से नुक्कड़ नाटक टीम एवं जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान मोनालिसा प्रशिक्षण एवं कल्याण संस्थान, बक्सर के सहयोग से जिले के विभिन्न गांवों में चलाया जाएगा। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को आग लगने की स्थिति में अपनाए जाने वाले आवश्यक उपायों, प्राथमिक सतर्कता और अग्निशमन यंत्रों के सही उपयोग की जानकारी दी जाएगी। अभियान का उद्देश्य लोगों को व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित करना है ताकि किसी भी आकस्मिक आगजनी की घटना में नुकसान को न्यूनतम किया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि विशेष रूप से आगामी पर्व-त्योहारों के दौरान तथा खेतों में पराली जलाने से होने वाली आग की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह पहल की गई है। उन्होंने बताया कि छोटी-सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है, इसलिए समय रहते सावधानी बरतना आवश्यक है। उन्होंने भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। श्रद्धालुओं, आयोजकों और आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे सतर्कता बरतें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि जिले का प्रत्येक नागरिक आग लगने की स्थिति में घबराने के बजाय सूझबूझ से कार्य करे और प्राथमिक बचाव के उपायों से परिचित रहे। अभियान के माध्यम से व्यापक स्तर पर जनजागरूकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि संभावित अग्निकांड की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके।

लाठी से हत्या मामले में ससुर को आठ वर्ष की सजा, डेढ़ लाख जुर्माना

केटी न्यूज/बक्सर

प्रधान जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने हत्या के एक चर्चित मामले में अभियुक्त हरी तुरहा को दोषी ठहराते हुए आठ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर कुल डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुमार्ना अदा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी। अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि घटना 8 जून 2010 की है। इटाढ़ी थाना क्षेत्र की निवासी सोनी देवी ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया था कि उसके ससुर हरी तुरहा ने उसके पुत्र को लाठी से मारकर उसकी हत्या कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इटाढ़ी थाना में संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी और पुलिस ने अनुसंधान कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और परिस्थितिजन्य प्रमाणों का गहन परीक्षण किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आठ वर्ष की सजा और एक लाख रुपये का जुमार्ना तथा धारा 201 के तहत एक वर्ष की सजा एवं पचास हजार रुपये का जुमार्ना निर्धारित किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

लोक शिकायतों पर सख्त दिखीं डीएम साहिला, तीन मामलों का मौके पर निपटारा

केटी न्यूज/बक्सर

समाहरणालय परिसर स्थित सभाकक्ष में गुरुवार को जिलाधिकारी साहिला ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील मामलों की सुनवाई की। सुनवाई ऑफलाइन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग–दोनों माध्यमों से की गई, जिससे विभिन्न प्रखंडों और नगर निकायों के पदाधिकारी भी सीधे तौर पर जुड़े रहे।

इस दौरान कुल 09 मामलों पर विस्तार से विचार किया गया। सभी मामले लोक शिकायत अधिकार निवारण से संबंधित थे। जिलाधिकारी ने प्रत्येक परिवाद की बिंदुवार समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों से जवाब तलब किया और लंबित मामलों में अनावश्यक देरी पर नाराजगी जताई। सुनवाई के क्रम में 03 मामलों का निष्पादन मौके पर ही कर दिया गया, जबकि शेष मामलों में संबंधित पदाधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

डीएम ने स्पष्ट कहा कि लोक शिकायत निवारण व्यवस्था आम नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाने का प्रभावी माध्यम है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रथम स्तर पर ही शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान करें, ताकि मामलों को द्वितीय अपील तक न आना पड़े।

बैठक में स्थापना उप समाहर्ता बक्सर एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल बक्सर सभाकक्ष में उपस्थित रहे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बक्सर, अंचलाधिकारी बक्सर, इटाढ़ी व नावानगर तथा थानाध्यक्ष वासुदेवा ओपी जुड़े रहे।

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों के निष्पादन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई कर अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने दोहराया कि जन समस्याओं के समाधान में प्रशासन की संवेदनशीलता ही सुशासन की पहचान है।

अयोध्या सा सजा ठोरी पांडेयपुर, रामलला की बाल लीलाओं से गूंजा गांव

केटी न्यूज/चौगाई

ठोरी पांडेयपुर गांव इन दिनों भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर है। गौरीशंकर, राधेकृष्ण मंदिर पश्चिम पोखरा परिसर में चल रही पांच दिवसीय श्रीराम कथा के तीसरे दिन गुरुवार को ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरा गांव अयोध्या में परिवर्तित हो गया हो। श्रीराम जन्म और उनकी मनोहारी बाल लीलाओं के प्रसंग ने श्रद्धालुओं के हृदय में भक्ति की ऐसी अलख जगाई कि देर शाम तक कथा स्थल ह्लजय श्रीरामह्व के उद्घोष से गूंजता रहा। राष्ट्रीय कथावाचक पंडित मधुसूदन बिहारी जी ने जब भगवान श्रीराम के अवतरण का प्रसंग सुनाया तो वातावरण भावविभोर हो उठा। उन्होंने अपने ओजस्वी और मधुर वाचन में बताया कि त्रेता युग में जब अयोध्या नगरी में रामलला ने जन्म लिया, तब सम्पूर्ण सृष्टि आनंद से भर उठी थी। देवताओं ने पुष्पवर्षा की, गंधर्वों ने मंगलगान किया और अयोध्या वासियों ने दीप प्रज्वलित कर उत्सव मनाया। कथावाचक के भावपूर्ण वर्णन से श्रोताओं को ऐसा अनुभव हुआ मानो वे स्वयं उस दिव्य क्षण के साक्षी हों। कथा का मुख्य आकर्षण श्रीराम की बाल लीलाओं का विस्तृत वर्णन रहा। पंडित जी ने रामलला के चंचल और मनोहारी बाल स्वरूप, माता कौशल्या के वात्सल्य और स्नेह, तथा गुरु वशिष्ठ के आश्रम में प्राप्त संस्कारों का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया। उन्होंने कहा कि श्रीराम केवल एक अवतार नहीं, बल्कि आदर्श जीवन के प्रतीक हैं। बाल्यकाल से ही उनमें आज्ञाकारिता, मयार्दा, संयम और करुणा के गुण विद्यमान थे, जो हर युग के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।

कथावाचन के दौरान संगीतमय प्रस्तुति ने श्रद्धा का वातावरण और भी सघन बना दिया। भजन और मंगल गीतों पर श्रद्धालु झूम उठे। महिलाएं मंगलगान करती रहीं तो युवा वर्ग भी पूरे उत्साह से कथा श्रवण में लीन दिखा। कई श्रद्धालुओं की आंखें भावुक होकर नम हो गईं।

आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि यह कथा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि समाज को नैतिकता और संस्कारों से जोड़ने का प्रयास है। उनका कहना है कि आज के दौर में श्रीराम के आदर्शों को आत्मसात करना ही सच्ची भक्ति है। कथा स्थल की सजावट, प्रकाश व्यवस्था और भक्तों की सेवा व्यवस्था भी आकर्षण का केंद्र बनी रही।

सबका सम्मान- जीवन आसान के तहत करहंसी पंचायत में लगा जनसमस्या समाधान शिविर

■ डीएम साहिला ने किया निरीक्षण, 48 घंटे में आवेदनों पर कार्रवाई का निर्देश, अनुपस्थित कनीय अभियंता से मांगी जाएगी जवाबदेही

केटी न्यूज/बक्सर

सात निश्चय 3.0 के अंतर्गत संचालित सबका सम्मान, जीवन आसान कार्यक्रम के तहत आम नागरिकों की दैनिक समस्याओं के त्वरित समाधान एवं पात्र लाभुकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करने के उद्देश्य से जिले की विभिन्न पंचायतों में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को बक्सर प्रखंड की करहंसी ग्राम पंचायत स्थित पंचायत भवन में आयोजित शिविर का जिलाधिकारी साहिला ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम को बताया गया कि निर्धारित समयावधि तक कुल 09 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों में जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित समस्याएं एवं मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मामले शामिल हैं। जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को सभी आवेदनों पर 48 घंटे के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिविर का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

डीएम ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया कि शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। उन्होंने सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, ममता, टोला सेवक समेत अन्य जमीनी स्तर के कर्मियों के माध्यम से ग्रामीणों को शिविर की जानकारी देने और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उपस्थित होने हेतु प्रेरित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। निरीक्षण के क्रम में कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के अनुपस्थित पाए जाने पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त की और कारण पृच्छा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल बक्सर को भी निर्देशित किया कि शिविर में प्राप्त नल-जल योजना की मरम्मत संबंधी आवेदनों पर 48 घंटे के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। जिला पदाधिकारी ने शिविर में उपस्थित अधिकारियों से कहा कि आमजन की शिकायतों को गंभीरता से लें और समाधान की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि शिविरों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और प्रगति प्रतिवेदन जिला स्तर पर उपलब्ध कराया जाए।

इस अवसर पर अपर समाहर्ता बक्सर, जिला जन संपर्क पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी बक्सर, अंचलाधिकारी बक्सर सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासन की ओर से बताया गया कि आगामी दिनों में भी अन्य पंचायतों में इसी प्रकार के शिविर आयोजित कर आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

ज्योति चौक पर जाम, कई प्रदर्शनकारी हिरासत में, निजीकरण और श्रम कानूनों में बदलाव के विरोध में ट्रेड यूनियनों का शक्ति प्रदर्शन

लेबर कोड के खिलाफ उबाल : चौसा थर्मल प्लांट प्रभावित, बक्सर में सड़क पर उतरे मजदूर

केटी न्यूज/बक्सर

केंद्र सरकार की श्रम नीतियों के खिलाफ गुरुवार को बक्सर में मजदूर संगठनों का गुस्सा खुलकर सड़कों पर दिखाई दिया। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर आयोजित अखिल भारतीय आम हड़ताल का जिले में व्यापक असर देखने को मिला। हड़ताल के कारण चौसा स्थित थर्मल पावर प्लांट का कामकाज प्रभावित रहा, जबकि शहर के व्यस्त ज्योति चौक पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर प्रशासन और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की।

सुबह से ही विभिन्न श्रमिक संगठनों से जुड़े मजदूर चौसा थर्मल पावर प्लांट के बाहर जुटने लगे। काम ठप रहने से उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि चार नए लेबर कोड लागू कर केंद्र सरकार ने दशकों से चले आ रहे 29 श्रम कानूनों को खत्म कर दिया है, जिससे मजदूरों की सुरक्षा और अधिकार कमजोर होंगे।

राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) सहित कई ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए श्रमिकों की मांगों को रखा। यह ज्ञापन एसटीपीएल के एचआर हेड कुलदीप राज को सौंपा गया। ज्ञापन में श्रम कानूनों की बहाली, मनरेगा में किए गए बदलावों को वापस लेने, सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण पर रोक और न्यूनतम वेतन की कानूनी गारंटी की मांग प्रमुख रूप से शामिल रही।

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भाकपा माले के जिला सचिव नवीन कुमार ने कहा कि चार लेबर कोड मजदूरों को असुरक्षित और मालिकों पर निर्भर बना देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि नई नीतियां श्रमिक हितों की अनदेखी कर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई हैं। उनके अनुसार, ह्लयह लड़ाई केवल मजदूरों की नहीं, बल्कि देश की आर्थिक दिशा को बचाने की है।ह्व

दोपहर तक आंदोलन शहर के ज्योति चौक पहुंच गया, जहां प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया। चौक पर यातायात बाधित होते ही लंबी कतारें लग गईं और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारी सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे और मांग कर रहे थे कि उनकी आवाज को गंभीरता से सुना जाए।

सड़क जाम की सूचना मिलते ही नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने पहले समझाने-बुझाने का प्रयास किया और सड़क खाली करने की अपील की। हालांकि प्रदर्शनकारी गिरफ्तारी देने की बात पर अड़े रहे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया। इसके बाद जाम समाप्त हुआ और यातायात सामान्य हो सका।

श्रमिक नेताओं ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक दायरे में है। उनका कहना है कि सरकार यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं करती है तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। नेताओं ने रेल चक्का जाम जैसे बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी।

हड़ताल का असर केवल औद्योगिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह राजनीतिक संदेश भी दे गया। जिले में मजदूर संगठनों की एकजुटता ने यह संकेत दिया कि श्रम कानूनों और निजीकरण के मुद्दे पर असंतोष गहराता जा रहा है।

हालांकि प्रशासन की ओर से कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि किसी को भी शांति भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए चार लेबर कोड, वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियां संहिताकृको लेकर देशभर में बहस जारी है। ट्रेड यूनियनें इन्हें मजदूर विरोधी बता रही हैं, जबकि सरकार इन्हें श्रम सुधार की दिशा में बड़ा कदम करार देती है।

बक्सर में हुए इस शक्ति प्रदर्शन ने साफ कर दिया है कि श्रमिक संगठनों का विरोध फिलहाल थमने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में यह आंदोलन किस दिशा में जाता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं।

एक नजर

लोक शिकायतों पर सख्त दिखीं डीएम साहिला, तीन मामलों का मौके पर निपटारा

बक्सर। समाहरणालय परिसर स्थित सभाकक्ष में गुरुवार को जिलाधिकारी साहिला ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील मामलों की सुनवाई की। सुनवाई ऑफलाइन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग– दोनों माध्यमों से की गई, जिससे विभिन्न प्रखंडों और नगर निकायों के पदाधिकारी भी सीधे तौर पर जुड़े रहे। इस दौरान कुल 09 मामलों पर विस्तार से विचार किया गया। सभी मामले लोक शिकायत अधिकार निवारण से संबंधित थे। जिलाधिकारी ने प्रत्येक परिवाद की बिंदुवार समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों से जवाब तलब किया और लंबित मामलों में अनावश्यक देरी पर नाराजगी जताई। सुनवाई के क्रम में 03 मामलों का निष्पादन मौके पर ही कर दिया गया, जबकि शेष मामलों में संबंधित पदाधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। डीएम ने स्पष्ट कहा कि लोक शिकायत निवारण व्यवस्था आम नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाने का प्रभावी माध्यम है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रथम स्तर पर ही शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान करें, ताकि मामलों को द्वितीय अपील तक न आना पड़े। बैठक में स्थापना उप समाहर्ता बक्सर एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल बक्सर सभाकक्ष में उपस्थित रहे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बक्सर, अंचलाधिकारी बक्सर, इटाढ़ी व नावानगर तथा थानाध्यक्ष वासुदेवा ओपी जुड़े रहे। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों के निष्पादन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई कर अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने दोहराया कि जन समस्याओं के समाधान में प्रशासन की संवेदनशीलता ही सुशासन की पहचान है।

राजपुर सीएचसी में चिकित्सकों की कमी गहराई 245 गांवों की स्वास्थ्य व्यवस्था पर संकट

राजपुर। राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में चिकित्सकों की कमी एक बार फिर गंभीर चिंता का विषय बन गई है। चिकित्सा प्रभारी डॉ. अशोक कुमार को जिला सदर अस्पताल में पूर्णकालिक प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने के बाद यहां स्वास्थ्य सेवाएं लगभग एक डॉक्टर के भरोसे सिमट गई हैं। ऐसे में प्रखंड के लगभग 245 गांवों की लाखों की आबादी की चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। अब तक डॉ. अशोक कुमार के नेतृत्व में अस्पताल का संचालन सुचारू रूप से हो रहा था। वे सप्ताह में एक दिन सदर अस्पताल में सेवाएं देते थे, लेकिन पूर्णकालिक तबादले के बाद राजपुर सीएचसी में नियमित चिकित्सक की उपलब्धता पर प्रश्नचिह्न लग गया है। वर्तमान में डॉ. सुनील कुमार और एक आयुष चिकित्सक के सहारे अस्पताल चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि डॉ. सुनील कुमार भी अस्वस्थ रहते हैं, जिससे मरीजों को समुचित उपचार नहीं मिल पा रहा है। हालांकि यहां नियमित टीकाकरण, पल्स पोलियो, कुष्ठ उन्मूलन समेत विभिन्न स्वास्थ्य योजनाएं आशा कर्मियों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के सहयोग से संचालित हो रही हैं, लेकिन विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव में गंभीर मरीजों को रेफर करना मजबूरी बन गई है। खासकर हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं होने से सड़क दुर्घटनाओं में घायल मरीजों को तत्काल राहत नहीं मिल पाती। बक्सर-कोचस मुख्य मार्ग पर आए दिन हो रही दुर्घटनाओं के मद्देनजर स्थानीय लोगों की चिंता और बढ़ गई है। पिछले सप्ताह हुई घटनाओं में एक युवक की मौत और कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। पूर्व मुखिया सत्येंद्र नारायण सिंह, पैक्स अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह समेत कई जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकताओं ने चेतावनी दी है कि यदि राजपुर सीएचसी में स्थायी रूप से चिकित्सक की तैनाती नहीं की गई तो जनआंदोलन किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डुमरांव उप प्रमुख चुनाव की जंग तेज

डुमरांव। डुमरांव प्रखंड की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसएलपी (सिविल) संख्या 12490/2024 में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के पूर्व स्थगन आदेश को निलंबित किए जाने के बाद प्रमुख एवं उप प्रमुख पद को लेकर सत्ता संतुलन की नई जंग शुरू होती दिख रही है। न्यायालय के ताजा आदेश ने लंबे समय से लंबित राजनीतिक गतिरोध को नई दिशा दे दी है। गौरतलब है कि 12 अक्टूबर 2024 को प्रखंड प्रमुख एवं उप प्रमुख के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव भारी मतों से पारित हुआ था। इसके बाद प्रमुख ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जहां से अविश्वास प्रस्ताव पर रोक लगा दी गई थी। इस रोक के कारण पद को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट के स्थगन आदेश को निलंबित किए जाने से अविश्वास प्रस्ताव फिर प्रभावी होता नजर आ रहा है। इसी क्रम में कोरानसराय पंचायत की बीडीसी सदस्य सबिता पासवान ने बुधवार शाम कार्यपालक पदाधिकारी सह बीडीओ को आवेदन देकर प्रमुख एवं उप प्रमुख पद को शक्तिमुक्त घोषित करने और पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 40(1)(ग) के तहत कार्यवाहक प्रमुख के चयन की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जब तक राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथि घोषित नहीं की जाती, तब तक प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए कार्यवाहक व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। बताया जाता है कि अक्टूबर 2024 में सबिता पासवान की अध्यक्षता में 18 पंचायत समिति सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था।

पंचायत स्तरीय शिविर में उमड़ी भीड़ कई आवेदनों का ऑन द स्पॉट निष्पादन

केटी न्यूज/डुमरांव

जिला प्रशासन बक्सर के निर्देश पर बिहार सरकार के सात निश्चय-3 के अंतर्गत संचालित ह्लसबका सम्मान, जीवन आसानह्व कार्यक्रम के तहत गुरुवार को प्रखंड क्षेत्र की कोरान सराय, मठीला एवं मुगांव पंचायतों में पंचायत स्तरीय जनसमस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य आम नागरिकों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं का त्वरित निराकरण करते हुए पात्र लाभुकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से आच्छादित करना था। शिविर में जन्म प्रमाण पत्र, आरटीपीएस से संबंधित आवेदन, शौचालय निर्माण,

प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषि कार्य हेतु विद्युत कनेक्शन सहित अन्य योजनाओं से जुड़े दर्जनों आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों में कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर लाभुकों को राहत प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया, जहां लोगों की प्राथमिक स्वास्थ्य जांच की गई। साथ ही किसान पंजीकरण (फार्मर रजिस्ट्रेशन) का कार्य भी संपन्न कराया गया। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कोरान सराय पंचायत में कुल 24 आवेदन मिले, जिनमें से 5 आवेदनों का तत्काल निष्पादन किया गया। वहीं मुगांव पंचायत में 46 तथा मठीला पंचायत में 19 आवेदन प्राप्त हुए। संबंधित विभागों के कर्मियों ने आवेदनों की जांच कर आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ की। शिविर के दौरान कई प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने शिविर का पर्यवेक्षण करते हुए अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और लोगों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े।

आईटीआई में बन रहे अटल कला भवन व खेल मैदान का डीएम ने किया निरीक्षण

■ लापरवाही पर कनीय अभियंता से कारण पृच्छा, नगर परिषद को सफाई व जल निकासी दुरुस्त करने का निर्देश

केटी न्यूज/बक्सर

जिलाधिकारी साहिला ने गुरूवार को आईटीआई परिसर में निमार्णाधीन अटल कला भवन एवं खेल मैदान का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

डीएम ने भवन प्रमंडल बक्सर के कार्यपालक अभियंता को योजना के कार्य में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित

किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास योजनाओं में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के क्रम में निर्माण कार्य में लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने भवन निर्माण निगम के कनीय अभियंता से कारण पृच्छा करने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि कार्य में देरी या अनियमितता के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

खेल मैदान की स्थिति का जायजा लेते हुए जिलाधिकारी ने नगर परिषद बक्सर के कार्यपालक पदाधिकारी को मैदान की समुचित साफ-सफाई कराने तथा जल निकासी की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि खेल मैदान युवाओं के शारीरिक विकास का महत्वपूर्ण केंद्र होता है, इसलिए इसकी उपयोगिता और सौंदर्य बनाए रखना आवश्यक है। साथ ही मैदान की चाहरदीवारी के समीप किए गए अस्थायी अतिक्रमण को यथाशीघ्र हटाने का भी निर्देश दिया, ताकि मैदान का क्षेत्र सुरक्षित और व्यवस्थित रह सके।

खेल मैदान के कार्यों के अनुश्रवण और प्रगति की नियमित समीक्षा के लिए उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा, बक्सर को विशेष रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई। डीएम ने उन्हें निर्देश दिया कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता पर सतत निगरानी रखें तथा प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराएं।

निरीक्षण के उपरांत जिला पदाधिकारी ने हवाई अड्डा परिसर का भी दौरा किया। वहां हवाई अड्डा पथ की जर्जर स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को शीघ्र मरम्मत कार्य कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही जल जमाव की समस्या के समाधान हेतु प्रभावी जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा, ताकि आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

जिला पदाधिकारी के निरीक्षण से संबंधित विभागों में सक्रियता देखी गई। उन्होंने दोहराया कि जिले में चल रही सभी विकास योजनाओं को समय पर पूर्ण कर आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।

पुलिस की मुस्तैदी से घंटेभर में बरामद हुई चोरी गई दो भैंस

केटी न्यूज/राजपुर

राजपुर थाना क्षेत्र के सरेंजा गांव में पशु चोरी की वारदात को पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने नाकाम कर दिया। किसान मनोज यादव के दरवाजे से चोरी हुई दो भैंसों को पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में बरामद कर लिया। इस कार्रवाई से जहां चोरों के मंसूबों पर पानी फिर गया, वहीं ग्रामीणों में पुलिस के प्रति विश्वास भी मजबूत हुआ है। जानकारी के अनुसार, बुधवार की रात मनोज यादव ने रोज की तरह पशुओं को चारा-पानी देकर दरवाजे पर बांध दिया था। देर रात अज्ञात चोर अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों भैंस खोल ले गए। कुछ देर बाद नींद खुलने पर जब भैंसें गायब मिलीं तो किसान के होश उड़ गए। परिजनों और पड़ोसियों के साथ उन्होंने तत्काल खोजबीन शुरू की, लेकिन गांव में कोई सुराग नहीं मिला।

इसी दौरान खोजते-खोजते वे

मुख्य सड़क की ओर पहुंचे, जहां गश्ती पर निकले थानाध्यक्ष निवास कुमार की नजर उन पर पड़ी। पूछताछ में चोरी की जानकारी मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। किसान को साथ लेकर पुलिस टीम ने संभावित मार्गों पर घेराबंदी करते हुए तलाश शुरू की। चौसा-मोहनिया मार्ग पर सोनपा पुल के समीप दबाव बढ़ता देख चोर भैंसों को छोड़कर अंधेरे का लाभ उठाते हुए फरार हो गए। पुलिस ने दोनों भैंस सुरक्षित बरामद कर किसान को सौंप दिया। ग्रामीणों ने पुलिस की तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि यदि इसी तरह गश्त और कार्रवाई जारी रही तो क्षेत्र में पशु चोरी जैसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगेगा। इस घटना ने साफ कर दिया है कि सक्रिय पुलिसिंग से अपराधियों के हौसले पस्त किए जा सकते हैं।

बिहार में सड़कों की ऊंचाई बढ़ाने पर सख्ती, पथ निर्माण विभाग ने जारी किया नया आदेश

एजेंसी। पटना

बिहार में शहरी क्षेत्रों में सड़कों की ऊंचाई मनमाने तरीके से बढ़ाने पर अब सख्ती बरती जाएगी। राज्य के पथ निर्माण विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बिना विभागीय अनुमति और उचित दस्तावेज के किसी भी स्थिति में सड़कों का लेवल (ऊंचाई) नहीं बढ़ाया जाएगा। शहरों में लगातार बढ़ रही जलजमाव की समस्या को देखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। विभाग के अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त की ओर से जारी पत्र में सभी संबंधित इंजीनियरों को निर्देश दिया गया है कि वे नए नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि पटना उच्च न्यायालय में

शहरी क्षेत्रों में जलजमाव को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी सड़कों का लेवल अनियंत्रित रूप से बढ़ाने पर रोक लगाने और ड्रेनेज व्यवस्था को बेहतर बनाने का निर्देश दिया था। इसी निर्देश के अनुपालन में विभाग ने सड़क निर्माण और मरम्मत से जुड़े कई नए मानक तय किए हैं। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब किसी भी सड़क के निर्माण या मरम्मत से पहले टोपोग्राफिक सर्वे कराना अनिवार्य होगा। इस सर्वे के जरिए इलाके की भौगोलिक स्थिति, ढाल, जल निकासी की दिशा और आसपास की संरचनाओं का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि सड़क निर्माण या मरम्मत का कार्य केवल सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही किया जाए।विभाग ने गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूत बनाने के लिए क्वालिटी कंट्रोल टीम को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। यह टीम टोपोग्राफिक सर्वे रिपोर्ट की जांच करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार ही हो रहा है या नहीं। साथ ही निर्माण के दौरान रोड प्रोफाइल का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण देने के भी निर्देश जारी किए गए हैं ताकि तकनीकी त्रुटियों को रोका जा सके। नए मानकों के तहत सड़क मरम्मत की प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब मरम्मत के दौरान केवल ऊपर नई परत चढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। बल्कि पहले सड़क की ऊपरी और पुरानी परतों को पूरी तरह हटाया जाएगा। इसके बाद नीचे की मूल परत से सड़क का निर्माण या मरम्मत की जाएगी। इससे सड़क की ऊंचाई अनावश्यक रूप से बढ़ने से रोकी जा सकेगी और जल निकासी की व्यवस्था भी प्रभावित नहीं होगी। इसके अलावा विभाग ने आबादी वाले इलाकों और बाजार क्षेत्रों में सड़क किनारे ड्रेनेज सिस्टम बनाना अनिवार्य कर दिया है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सड़क निर्माण के दौरान जल निकासी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि बारिश के समय पानी जमा होने की समस्या उत्पन्न न हो। बाजार क्षेत्रों में फुटपाथ या रैम्प का निर्माण भी अनिवार्य किया गया है, जिससे पैदल चलने वाले लोगों और और दुकानदारों को सुविधा मिल सके। शहरी सड़कों की ऊंचाई बढ़ने से जलजमाव की समस्या का मुद्दा हाल ही में बिहार विधान परिषद में भी उठा था। परिषद में इस विषय को लेकर सदस्य अब्दुल बारी सिद्दिकी ने सवाल उठाते हुए कहा था कि कई जगह सड़कों को ऊंचा करने से ड्रेनेज बाधित हो रहा है, जिसके कारण बारिश के दौरान पानी घरों और बाजारों में जमा हो जाता है।

बिहार के ग्रामीण इलाकों की बदलेगी पुलिसिंग
11 ग्रामीण एसपी को मिले नए अधिकार और जिम्मेदारी

एजेंसी। पटना

बिहार में ग्रामीण इलाकों की पुलिसिंग को और सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। गृह विभाग ने 11 जिलों में नियुक्त ग्रामीण एसपी के क्षेत्राधिकार और अधिकार स्पष्ट करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण, थानों की निगरानी और प्रशासनिक कार्रवाई की जिम्मेदारी अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह तरीके से तय की गई है।पुलिस महकमा ने राज्य में बेहतर और मुस्तैद पुलिसिंग के लिए राज्य में 11 जिलों में निर्धारित ग्रामीण एसपी (पुलिस अधीक्षक) के क्षेत्राधिकार को निर्धारित करते हुए उनके अधिकार स्पष्ट कर दिए गए हैं। इससे संबंधित अधिसूचना गृह विभाग ने जारी कर दी है। इसके अनुसार, 2022 में गठित ग्रामीण एसपी के 11 अलगझ्रअलग पदों के अधीन आने वाले अनुमंडल और उनके अंतर्गत आने वाले थानों की संख्या का निर्धारण किया गया है। संबंधित जिलों के एसपी कार्यालयों के शाखाओं का बंटवारा एसपी (ग्रामीण) और अन्य के बीच करेंगे। गया के ग्रामीण एसपी के कार्य क्षेत्र में अब नीमचक बथानी के एसडीपीओ, टिकारी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ), इमामगंज के एसडीपीओ, शेरघाटीझ्र1 एवं शेरघाटीझ्र2 के एसडीपीओ के साथ ही इनके अधीन आने वाले सभी थाने। इन सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अधीन करीब 33 थाने हैं, जो ग्रामीण एसपी के अधीन हो जाएंगे। रोहतास एसपी (ग्रामीण) के अधीन सासाराम मुख्यालय कोचस के एसडीपीओ, 2, डिहरी एसडीपीओ, 2 और विक्रमगंज एसडीपीओ के साथ ही आने वाले सभी 28 थाने।

मुंगेर (ग्रामीण) एसपी के तहत सदर एसडीपीओ, तारापुर एसडीपीओ और हवेली खड़गपुर एसडीपीओ और इनके अधीन आने वाले 12 थाने। बेगूसराय के एसपी (ग्रामीण) के अंतर्गत मंझौल एसडीपीओ, बखरी एसडीपीओ और बलिया एसडीपीओ के साथ ही इनसे जुड़े 11 थाने शामिल हैं। भागलपुर एसपी (ग्रामीण) के अंतर्गत कहलगांव, 1 एवं कहलगांव, 2 के एसडीपीओ और भागलपुर विधि-व्यवस्था डीएसपी और इनके अंतर्गत आने वाले 18 थाने। पूर्णिया ग्रामीण एसपी के अंतर्गत बायसी, बनमनखी और धमदाहा एसडीपीओ और इनके अधीन आने वाले 18 थाने। सहरसा एसपी (ग्रामीण) के अंतर्गत सिमरी बख्तियारपुर एसडीपीओ और इनके अधीन के 9 थाने शामिल हैं। दरभंगा एसपी (ग्रामीण) के अंतर्गत आने वाले बेनीपुर, बिरौल एसडीपीओ एवं सदर के एसडीपीओ, 2 और इनके तहत आने वाले 19 थाने। मुजफ्फरपुर के एसपी (ग्रामीण) के तहत पूर्वी, 1, पूर्वी, 2 और सरैया के एसडीपीओ के अलावा इनके अधीन आने वाले 24 थाने शामिल हैं। सारण के ग्रामीण एसपी के अधीन मढ़ौराझ्र 1, मढ़ौरा, 2 एवं सोनपुर के एसडीपीओ और उनके अधीन आने वाले 18 थाने शामिल हैं। बेतिया के एसपी ग्रामीण के अधीन सदर, 2 और नरकटियागंज के एसडीपीओ तथा इनके अधीन आने वाले 21 थाने आते हैं।

ये होंगे अधिकार

गृह विभाग ने सितंबर 2022 में बिहार पुलिस सेवा संवर्ग के अंतर्गत 181 पदों का सृजन किया गया था। इसमें ग्रामीण एसपी के 11 पद भी शामिल हैं। अब इनके अधिकार और कार्य क्षेत्र का भी निर्धारण कर दिया गया है। अपने क्षेत्र के अधीन आने वाले प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, कांडों की समीक्षा एवं अपराध नियंत्रण के साथ ही सभी महत्वपूर्ण विषयों से जिला एसपी को अवगत कराना। अपने अधीन थानों की अपराध पंजी, दैनिक प्रतिवेदन, पेट्रोलिंग चार्ट समेत अन्य का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करना। अपने क्षेत्राधिकार पदस्थापित दारोगा और उनके नीचे के पदाधिकारी (सिपाही और हवलदार) को निलंबित कर सकते हैं। पुलिस लाइन के पदाधिकारियों का निलंबन जिला एसपी से विमर्श करने के बाद कर सकते हैं। सप्ताह में कम से कम एक बार पुलिस परेड में भाग लेंगे। पुलिस सभा में मौजूद रहेंगे।

निःशुल्क विद्युत कनेक्शन शिविर से किसानों के बहुरेंगे दिन

केटी न्यूज/रजौली

प्रखंड क्षेत्र के मुरहेना पंचायत में किसानों के लिए शुक्रवार को विद्युत विभाग ने निःशुल्क शिविर का आयोजन किया। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत योजना फेज-2 के तहत आयोजित इस कैंप का मुख्य उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए पूरी तरह निःशुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान करना है,ताकि उन्हें कृषि क्षेत्र में किसी प्रकार की आर्थिक व तकनीकी समस्या से निजात मिले। इस संदर्भ में विद्युत अधिकारियों द्वारा दी जानकारी में इस योजना को जन-जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। ताकि अधिक से अधिक किसान इस सुविधा का लाभ उठा सकें। किसान मॉडर्न ट्रांसफार्मर प्राइवेट लिमिटेड के इंजीनियर नवलेश कुमार ने कहा कि आरडीएसएस परियोजना के तहत कृषि कार्यों के लिए अलग बिजली फीडर और मजबूत विद्युत संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है,जिससे सिंचाई के लिए निरंतर और

उच्च गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इच्छुक किसान शिविर और 'सुविधा ऐप' के माध्यम से भी अपना आवेदन दर्ज करा कनेक्शन ले सकते है। विभाग भी सक्रिय होते हुए कोई किसान सिंचाई के साधनों से वंचित न रहे इसके लिए विभिन्न पंचायतों में विशेष शिविरों का निरंतर आयोजन कर रही है।जारी रहेगा। साथ ही 'कुटीर ज्योति' श्रेणी के उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। घर की छतों पर सोलर प्लांट लगाने की पूरी प्रक्रिया, मिलने वाली सब्सिडी और तकनीकी बारीकियों की जानकारी भी इसी मंच से साझा की जाएगी,जिससे किसान न केवल अपनी फसलों को सींच सकेंगे बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

केसठ प्रखंड में जन शिकायत निवारण कैंप आयोजित
26 मामलों में 11 का ऑन द स्पॉट हुआ समाधान

केटी न्यूज/केसठ

राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सात निश्चय-3 के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़, संवेदनशील, रोजगारोन्मुख और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से ह्यसबका सम्मान-जीवन आसानह्न पहल के तहत केसठ प्रखंड में जन शिकायत निवारण कैंप का आयोजन किया गया। यह कैंप स्थानीय पंचायत के पंचायत सरकार भवन में आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे और संबंधित अधिकारियों के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया।

कैंप के दौरान सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मनरेगा, अंचल कार्यालय समेत विभिन्न विभागों से कुल 26 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 11 मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया, जिससे संबंधित लाभुकों को तत्काल राहत मिली। वहीं शेष मामलों को संबंधित विभागों को अग्रसारित कर दिया गया है, जिनका जल्द समाधान करने का आश्वासन

दिया गया।हालांकि कैंप के दौरान कई विभागों के पदाधिकारियों की अनुपस्थिति भी देखने को मिली, जिसके कारण कुछ मामलों का समाधान नहीं हो सका। इस स्थिति को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी भी देखी गई। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर जन शिकायत समाधान दिवस आयोजित करने का उद्देश्य तभी सार्थक होगा, जब सभी संबंधित विभागों के अधिकारी निर्धारित समय पर उपस्थित होकर लोगों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रशासन से कैंप की व्यवस्था को और प्रभावी बनाने तथा सभी विभागों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित कराने की मांग की।प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार सौरभ ने बताया कि सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। उन्होंने कहा कि जिन मामलों का निष्पादन मौके पर संभव नहीं हो सका है, उन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया गया है और उनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे अपनी समस्याओं को लेकर ऐसे कैंपों में भाग लें, ताकि प्रशासन को उनकी समस्याओं के समाधान में सुविधा हो सके।इस अवसर पर कार्यक्रम पदाधिकारी गौरव कुमार , पंचायत रोजगार सेवक जितेन्द्र कुमार सिंह, पप्पू खान, बिहारी सिंह सहित कई अन्य कर्मी एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।

एक नजर

वेतन भुगतान नहीं होने से आशा ने पीएचसी पर दिया धरना प्रदर्शन

तिलौथू । प्रखंड क्षेत्र के स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में 8 माह से मानदेय-वेतन का भुगतान नहीं होने से आक्रोशित आशा कार्यकताओं ने गुरुवार को पीएचसी में ताला जड़कर धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में मौजूद आशा कार्यकताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और अपनी मांगों को लेकर अडिग रहीं। धरना स्थल पर आशा कार्यकर्ता फुलकांति देवी ने कहा कि सरकार को हमारी कार्यस्थितियों की वास्तविकता का कोई अंदाजा नहीं है। आठ माह से वेतन बंद है, फिर भी हर सरकारी स्वास्थ्य अभियान में सबसे पहले आशा कार्यकताओं को ही लगाया जाता है। गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव हो, पोलियो ड्रॉप पिलाने का अभियान हो या वर्तमान में चल रहा फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम हर कार्य में आशा कार्यकताओं की भूमिका अहम होती है। उन्होंने कहा कि सरकार इन सभी अभियानों के आंकड़े गिनाकर अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन आशा कार्यकताओं की आर्थिक स्थिति और समस्याओं पर न तो स्वास्थ्य मंत्री और न ही मुख्यमंत्री कोई संज्ञान ले रहे हैं। यह पूरी तरह से निरंकुश रवैया है। आशा कार्यकताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा, तब तक वे काम नहीं करेंगी और न ही पीएचसी में नियमित कार्य संचालन होने देंगी। धरना-प्रदर्शन के दौरान पीएचसी परिसर में कार्य बाधित रहा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुईं। प्रदर्शनकारी आशा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर प्रशासन और सरकार से शीघ्र हस्तक्षेप की मांग कर रही हैं।

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दी गई भावभीनी विदाई

काराकाट। काराकाट मुख्यालय गोडारी स्थित प्रखंड संसाधन केंद्र में गुरुवार को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) मोहम्मद कलीमुद्दीन के सेवानिवृत्ति के अवसर पर विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में जिला भर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों, शिक्षकों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरूआत कस्तूरबा आवासीय विद्यालय जयश्री की छात्राओं ने स्वागत गीत से की। मंच संचालन मजहर हुसैन और एमएस काराकाट लक्की आलम ने संयुक्त रूप से किया। वक्ताओं ने बीईओ मो.कलीमुद्दीन के तीन वर्षीय कार्यकाल की खूब सराहना की। उन्होंने कहा कि उनका कार्यकाल अत्यंत सराहनीय रहा, जिसमें शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया गया। सभी शिक्षकों ने उनके कार्यकाल पर प्रकाश डालते हुए भावुक क्षण साझा किए। समारोह में बीडीओ राहुल कुमार सिंह भी शामिल हुए। पीएम पोषण प्रभारी काराकाट जाकिर हुसैन,सौंझौली बीईओ अफरोज आलम, तिलौथू बीईओ रजनीश कुमार, नोखा बीईओ सुमन श्रीवास्तव, दावथ बीईओ आनंद किशोर मिश्रा,शिवसागर बीईओ राजेश कुमार,राजपुर बीईओ प्रेम रंजन, काशीनाथ राम,ओमाशंकर, राजनाथ राम, अनिल कुमार पासवान, डाटा ऑपरेटर किसु कुमार सिंह, वार्डन गुड़िया पांडे, नाहिदा, छटो कुमारी, जयंत कुमार, आबिद हुसैन, मो. शमसाद अली सहित विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों ने शॉल और बुके भेंट कर उन्हें भावपूर्ण विदाई दी।काराकाट प्रखंड में शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। समारोह में उपस्थित सभी ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। यह आयोजन प्रखंड शिक्षा परिवार की एकजुटता का प्रतीक बना।

रोहतास डीएम की अध्यक्षता में अनुकंपा समिति पर बैठक आयोजन

सासाराम। गुरुवार को जिला पदाधिकारी उदिता सिंह की अध्यक्षता समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों यथा लिपिक, वाहन चालक एवं कार्यालय परिचारियों का अस्थायी व्यवस्था के तहत प्रोन्नति के पद का कार्यकारी प्रभार व वेतनमान सहित देने के निमित एवं एसीपी-एमएसीपी का लाभ तथा जिला अनुकम्पा समिति की बैठक आहूत की गयी। बैठक में अस्थायी व्यवस्था के तहत प्रोन्नति के पद का कार्यकारी प्रभार (वेतनमान सहित) देने के निमित लिपिक का 13 मामलों, वाहन चालक का 09 मामलों,कार्यालय परिचारियों का 26 मामलों का निष्पादन किया गया है। साथ ही एसीपी-एमएसीपी का लाभ के मामले में लिपिक का 18 एवं कार्यालय परिचारी का 12 मामलों, राजस्व कर्मचारी का 12 मामलों एवं चौकीदार के 198 मामलों का निष्पादन किया गया। मृत चौकीदारों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करने हेतु कुल 01 मामला का निष्पादन किया गया। अपर समाहर्त्ता सह अपर जिला दण्डाधिकारी रोहतास, उप विकास आयुक्त, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,अनुमण्डल पदाधिकारी सासाराम, स्थापना उप समाहर्त्ता, सहायक लेखा पदाधिकारी, कल्याण पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

छापेमारी कर पुलिस ने 81लीटर शराब किया बरामद

गडहनी । जिला क्षेत्र के अगिआंव थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार को थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। कार्रवाई के दौरान एक महिला को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्य आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक कमलजीत ने जानकारी देते हुए बताया कि पुअनि अर्जुन कुमार दास दिवा गश्ती के दौरान सशस्त्र बल के साथ अगिआंव दुर्गा मंदिर के समीप थे, तभी सूचना मिली कि डुमरिया निवासी अमित कुमार उर्फ बंटी अपने घर में अंग्रेजी शराब रखकर अपनी मां के साथ अवैध बिक्री कर रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम चौकीदार व सशस्त्र बल के साथ उसके घर पहुंची। पुलिस को देखते ही एक युवक घर बंद कर भागने लगा, जिसे पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन वह फरार हो गया। इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों को स्वतंत्र साक्षी बनाकर घर की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान अर्धनिर्मित मकान के एक कमरे के छज्जे पर रखे नौ कार्टून से विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस के अनुसार, बरामद शराब में रॉयल स्टैग प्रीमियर एवं रॉयल स्टैग डिलक्स व्हिस्की की कुल 81 लीटर शराब शामिल है। बरामदगी के बाद जप्ती सूची तैयार कर शराब जब्त कर ली गई तथा नमूना सुरक्षित रखा गया।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दिया आदेश
सरकारी जमीन जल्दी खाली कराएं सभी डीएम

एजेंसी। पटना

सूबे में सरकारी भूमि के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक सख्ती और तेज हो गई है। मुख्य सचिव, बिहार के पूर्व निदेशों तथा हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. कैडेस्ट्रल सर्वे में दर्ज सरकारी भूमि, जिस पर विधिसम्मत बंदोबस्ती नहीं हुई है और जो निजी व्यक्तियों के कब्जे में है, उसे प्राथमिकता के आधार पर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए मुक्त कराया जाए। यह निर्देश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने जारी किया है। बता दें, पिछले दो

माह के दौरान सरकारी भूमि की सुरक्षा को लेकर कई परिपत्र जारी किए जा चुके हैं। इसी क्रम में उच्चतम न्यायालय ने SLP (C) No. 4337/2025 (विनोद गाँधी बनाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मदुरई) मामले में 22 जनवरी 2026 को महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारियों की चूक या लापरवाही के कारण राज्य के हित प्रभावित नहीं होने चाहिए। निदेशों में कहा गया है कि ऐसी सभी सरकारी भूमि की पहचान कर विधिसम्मत कार्रवाई के तहत वाद दायर किए जाएं तथा भूमि की रिकवरी सुनिश्चित की जाए। सभी जिला प्रशासन को यह भी निर्देशित किया गया है कि इस कार्य को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए नियमित निगरानी की जाए। इन निर्देशों के मूल में अंचलवार सरकारी भूमि को सुरक्षित कर लैंड बैंक का निर्माण करना है, ताकि राज्य में औद्योगीकरण, आधारभूत संरचना विकास और जनकल्याणकारी परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। राज्य स्तर पर जारी इन सख्त निर्देशों से स्पष्ट है कि अब सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए सक्रिय कार्रवाई करेगा तथा न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगा। उप मुख्यमंत्री सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकारी भूमि राज्य की अमूल्य संपत्ति है। इस पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा न तो स्वीकार्य है और न ही सहनीय। उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के आलोक में हमने सभी जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कैडेस्ट्रल सर्वे में दर्ज ऐसी सरकारी भूमि, जिनका विधिसम्मत बंदोबस्ती नहीं हुआ है, उन्हें विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए प्राथमिकता के आधार पर मुक्त कराई जाए। राजस्व विभाग के मंत्री ने आगे कहा है कि अधिकारियों की किसी भी चूक या लापरवाही के कारण राज्य के हित प्रभावित नहीं होने दिए जाएंगे।

कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को निःशुल्क सोलर पैनल लगाने से खुशी

केटी न्यूज/रोहतास

रोहतास जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और वंचित परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब कुटीर ज्योति श्रेणी के उपभोक्ताओं की छत पर 1.1 केवीए का रूफटॉप सोलर पैनल बिल्कुल मुफ्त लगाया जाएगा,जिससे बिजली खर्च में कमी आएगी। विद्युत अधीक्षण अभियंता सासाराम ई. इंद्रदेव कुमार ने बताया की उपभोक्ताओं की सहमति मिलने के बाद उनके घर की छत पर सोलर पैनल स्थापित किया जाएगा। इसके लिए उपभोक्ताओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस योजना का मकसद ग्रामीण गरीब परिवारों को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। सोलर पैनल लगने से घरेलू बिजली जरूरतों को पूरा करना आसान होगा, साथ ही हर महीने आने वाले बिजली बिल से भी राहत मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का अधिक से अधिक इस्तेमाल हो। इंजीनियरों ने बताया कि सोलर ऊर्जा भविष्य की जरूरत है, इससे न केवल पर्यावरण को लाभ होगा बल्कि उपभोक्ताओं को लंबे समय तक सुरक्षित और टिकाऊ बिजली मिलेगी। सोलर पैनल से प्रदूषण भी नहीं होता, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया गया की प्रखंड बिक्रमगंज मे कुल 3922, दावथ मे 3257, दिनारा मे 11391,सूर्यपुरा मे 1967, संझौली मे 2907, कोचस मे 6252, करगहर मे 8269, शिवसागर मे 9554, चेनारी मे 5054, नोखा मे 7711 व सासाराम ग्रामीण में 6532 उपभोक्ता हैं। उक्त सभी उपभोक्ताओं को सुविधा एप्प के माध्यम से आवेदन करना होगा। सुविधा एप्प मे 'सोलर रूफ टॉप के लिए सहमति' चयन करने के उपरांत आवेदक को सहमति देना है की मेरे घर के छत पर सोलर प्लेट लगाने में मैं सहमत हूँ तथा रूफ टॉप सोलर को ठीक ठाक से रख रखाव करेंगे। पंजीकरण के बाद विभाग की टीम आगे की प्रक्रिया पूरी करेगी। किसी भी तरह की जानकारी या सहायता के लिए उपभोक्ता अपने नजदीकी बिजली कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। कुटीर ज्योति योजना भारत सरकार की एक पुरानी और अहम योजना है। इसे वर्ष 1988-89 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के घरों में एकल बिंदु बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना था। इस योजना से लाखों गरीब परिवारों के घरों में पहली बार रोशनी पहुंची। अब इसी कुटीर ज्योति योजना को सोलर ऊर्जा से जोड़ा गया है, इसके तहत 1.1 केवीए का सोलर प्लांट बिल्कुल मुफ्त लगाया जाएगा। इससे ग्रामीण परिवारों को नियमित और सस्ती बिजली मिलेगी। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार होगा और राज्य हरित ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए 28 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है।

बेतिया-कुमारबाग डबल रेल लाइन कार्य : वंदे भारत समेत कई ट्रेनें डायवर्ट, रद और लेट

एजेंसी। पटना

बेतिया-कुमारबाग के बीच डबल रेल लाइन बनकर तैयार हो चुकी है। सिग्नलिंग प्रणाली से जोड़ने के लिए गुरुवार से प्री-नॉन इंटरलॉकिंग शुरू हो गया है। इसको लेकर वंदे भारत सहित कई ट्रेनों को देरी से, रूट डावयर्ट तथा कई ट्रेनों को रद कर दिया गया है। बुधवार को पूर्वांचल एक्सप्रेस, नरकटियागंज-मुजफ्फरपुर पैसेंजर ट्रेन सहित अन्य कई ट्रेनें घंटों लेट हो गई। एनआई की सूचना रेलवे की ओर से जारी नहीं होने के कारण कई यात्रियों ने इसकी शिकायत इंटरनेट मीडिया पर की है। मुजफ्फरपुर में गोरखपुर से कोलकाता जाने वाली 15052 पूर्वांचल एक्सप्रेस की प्रतीक्षा में बैठे यात्री पुष्पम सान्याल ने बताया कि यह ट्रेन करीब चार घंटे लेट हो गई। इस ट्रेन को नरकटियागंज में एक घंटे की देरी कर दिया गया। उसके बाद यह ट्रेन देरी होती चली गई। यह ट्रेन शाम पांच बजे के बजाय रात को आठ बजे पहुंची।उसी तरह नरकटियागंज-मुजफ्फरपुर पैसेंजर ट्रेन नरकटियागंज से सवा दो घंटे लेट चली। इसके कारण यह ट्रेन शाम सात बजे तक मोतिहारी से भी पीछे थी।एक रेल अधिकारी ने बताया कि बेतिया-कुमारबाग के बीच सुबह साढ़े दस से दोपहर ढाई बजे तक चार घंटे का 240 मिनट का ब्लॉक लिया गया था। इसके कारण पूर्वांचल, नरकटियागंज-मुजफ्फरपुर पैसेंजर, अप अवध एक्सप्रेस, अप सप्तक्रांति एक्सप्रेस मोतिहारी से वाल्मीकिनगर के बीच एक से डेढ़ घंटे की देरी से चलाई गई। शुक्रवार को फिर इस रूट पर सुबह साढ़े दस से दोपहर ढ़ाई बजे तक चार घंटे का ब्लॉक रहेगा। इसके को लेकर 15216, 45 मिनट, 19038 डेढ़ घंटे, 12557 एक घंटे की देरी कर चलाई जाएगी। शनिवार को 63342 नरकटियागंज-मुजफ्फरपुर तथा 63309 मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज कैंसिल रहेगी। 63341 नरकटियागंज-मुजफ्फरपुर 60 मिनट की देरी से चलाई जाएगी। 19037 अवध एक्सप्रेस 60 मिनट, 19269 90 मिनट तथा 15273 डायवर्ट रूट, 19038 अवध एक्सप्रेस सीतामढ़ी होकर डायवर्ट, 12557 सुगौली, रक्सौल, सीतामढ़ी होकर डायवर्ट, 15706 सीतामढ़ी, 15215 मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज पैसेंजर ट्रेन, 15216 नरकटियागंज-मुजफ्फरपुर पैसेंजर ट्रेन डायवर्ट रूट से चलाई जाएगी।15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन सुबह नौ से शाम चार बजे तक नॉन इंटरलॉकिंग के लिए ब्लॉक रहेगा। इसको लेकर दो जोड़ी यानी चार पैसेंजर ट्रेनें रद रहेगी। इसमें 63342, 75236, 63309, 75235 पैसेंजर ट्रेन रद रहेगी। 26502 वंदे भारत ट्रेन, 09451, 15273,19038,12557,15274, 15002, 19037, 26501, 15212, 15211, 15516, 12558, 15568, 19270, 19269, 15215, 15216 डायवर्ट रूट से चलाई जाएगी। वहीं, 16 फरवरी को सुबह नौ से दोपहर तीन बजे तथा दूसरी ब्लॉक शाम चार से साढ़े पांच बजे तक रहेगी। इसको लेकर 63342, 75236, 63309, 75235 दोनों जोड़ी पैसेंजर ट्रेनें रद रहेगी। 63341 और 15202 देरी से चलाई जाएगी। इस रूट की अन्य ट्रेनें डायवर्ट और शार्ट टर्मिनेशन कर चलाई जाएगी।

नीट छात्रा मौत मामले को सीबीआई ने अपने हाथों में लिया, स्पेशल केस के तौर पर किया रजिस्टर

एजेंसी। पटना

पटना में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के हाथ में चला गया है। बिहार के अधिकारियों की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, सीबीआई ने इसे स्पेशल केस के रूप में दर्ज किया है और केस नंबर 7एस/26 रखा गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार के अधिकारियों की टीम दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय पहुंच गई है और जांच की शुरूआत कर दी गई है। इस घटना के बाद से ही इस मामले की जांच को लेकर सवाल उठ रहे थे। छात्रा के परिवार और समाज के विभिन्न वर्गों ने राज्य सरकार से सीबीआई जांच की मांग की थी। लगातार बढ़ते दबाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय सरकार से इस केस की सीबीआई जांच करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री के अनुरोध और राज्य सरकार की सिफारिश को मंजूरी मिलने के बाद ही सीबीआई ने इस मामले को अपने अधीन लिया। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए सम्राट चौधरी ने साझा की थी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के अनुरोध को मान्यता मिलने के बाद ही सीबीआई ने केस टेकओवर किया है और जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीबीआई की टीम अब मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। इसमें छात्रा के परिवार से पूछताछ, घटना स्थल का निरीक्षण, सीसीटीवी फुटेज की जांच, और अन्य सबूतों का विश्लेषण शामिल है। अधिकारियों का मानना है कि इस स्पेशल केस दर्ज करने का उद्देश्य जांच में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार ने कहा है कि जांच पूरी होने तक सभी संवेदनशील जानकारियों को गोपनीय रखा जाएगा। बिहार पुलिस की ओर से भी उइकको सभी आवश्यक दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि जांच जल्दी और प्रभावी ढंग से पूरी की जा सके। इस कदम से यह संदेश भी मिलता है कि राज्य सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियां गंभीर मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। मामले की जांच में जल्द ही महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस घटना ने पूरे राज्य में नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों और उनके परिवारों में चिंता पैदा कर दी थी। अब सीबीआई की जांच से यह स्पष्ट होगा कि छात्रा की मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही या अपराधी गतिविधि शामिल है या नहीं। राज्य सरकार और सीबीआई दोनों ही मामले की निष्पक्ष और शीघ्र जांच पर जोर दे रहे हैं, ताकि परिवार और समाज को न्याय मिल सके।

आखिर सीबीआई ने संभाली नीट अभ्यर्थी की हत्या की जांच, सीएम नीतीश ने खुद की थी अनुशंसा

पटना में एक नीट अभ्यर्थी की रहस्यमयी मौत के मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है और स्थानीय पुलिस से जांच अपने हाथ में ले ली है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।जहानाबाद की रहने वाली नीट अभ्यर्थी 6 जनवरी को पटना के चित्रगुप्त नगर स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल में बेहोशी की हालत में मिली थी। वह कोमा में चली गई थी और पांच दिन बाद एक निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस मौत के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई, जिसके चलते सरकार ने 31 जनवरी को मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी।लड़की के परिवार ने आरोप लगाया था कि उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया और मामले को दबाने की कोशिश की गई। पुलिस ने हॉस्टल के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया था।

एक नजर

क्रिकेट खेल कर लौट रहे बच्चों को तेज रफ़्तार वाहन ने रौंद डाला, तीन लोगों की हुई मौत

दरभंगा। बिहार के दरभंगा जिले के बिरौल-गंडोल मुख्य सड़क (एसएच-17) पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन किशोरों की मौत हो गई। ये तीनों युवक क्रिकेट खेलकर अपने घर लौट रहे थे। हादसा बिरौल थाना क्षेत्र के सोनपुर क्रॉसिंग के पास हुआ, जब एक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार तीनों किशोरों को अपनी चपेट में ले लिया। घटनास्थल पर ही तीनों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान बड़गांव थाना क्षेत्र के अखतवाड़ा गांव निवासी अंकित कुमार (17), पंकज कुमार सहनी (17) और विवेक कुमार (16) के रूप में हुई है। ये सभी किशोर होमगार्ड जवान बैजनाथ सहनी की बाइक पर सवार होकर अपने गांव से सुपौल बाजार की ओर जा रहे थे। हादसे के समय सामने से आ रहा अनियंत्रित वाहन उन्हें टक्कर मारते हुए मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तीनों शवों को सुपौल स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर से मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन अस्पताल पहुंच गए, जिससे वहां अफरातफरी का माहौल बन गया। अखतवाड़ा गांव में तीनों किशोरों की मौत से मातम पसरा हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि तीनों युवक होनहार और पढ़ाई-लिखाई में भी अच्छे थे। क्रिकेट खेलने के बाद घर लौटते समय यह हादसा हुआ। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। मृतक विवेक के चाचा और होमगार्ड के रिटायर्ड जवान बैद्यनाथ सहनी ने कहा कि परिवार ने तीनों को बाजार जाने से मना किया था, लेकिन वे अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे। मौत ने सभी को अपनों से दूर ले जाकर घरों में मातम फैला दिया। बिरौल थाना के थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन की पहचान के लिए पुलिस सघन जांच कर रही है और जल्द ही चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

सहरसा में विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद, होली में खपाने की थी तैयारी

सहरसा। बिहार में शराबबंदी पिछले 10 साल से लागू है, लेकिन इसके बावजूद आए दिन शराब की खेप पकड़ी जा रही है। इस बार होली में खपाने के उद्धेश्य से शराब लाई गयी थी। सहरसा जिले में ऊ्व सहरसा और बिहरा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया है। यह कार्रवाई बिहरा थाना क्षेत्र के पटोरी गांव में की गई। थानाध्यक्ष शशि कुमार राणा ने बताया कि डीईयू टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि दरभंगा से बनगांव होते हुए सुपौल की ओर एक ट्रक में अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप ले जाई जा रही है। सूचना मिलते ही डीईयू टीम ने बिहरा थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद संयुक्त रूप से ट्रक का पीछा किया गया।पटोरी बाजार स्थित एसबीआई बैंक पोखर के पास ट्रक संख्या JH 10 DC 5776 को पकड़ा गया। ट्रक को थाना लाकर जब तलाशी ली गई तो उसमें तहखाना बनाकर छिपाई गई 60 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। शराब की पेटियों को ऊपर से मोटी चादर से ढंका गया था ताकि किसी को शक न हो। जांच के दौरान पाया गया कि प्रत्येक पेटी में 180 एमएल की व्हिस्की की 48 बोतलें थीं। कुल 2880 बोतलें यानी 518.400 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई। पुलिस ने ट्रक और शराब को जब्त कर लिया है तथा चालक मो. कलाम (निवासीझ दुमका) को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बिहरा थाना क्षेत्र में इतनी बड़ी मात्रा में शराब बरामद होने से पुलिस महकमे में हलचल है, वहीं यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।

सुपौल में भीषण सड़क हादसा : दो बाइकों की सीधी टक्कर में तीन युवकों की दर्दनाक मौत, 2 की हालत गंभीर

एजेंसी। पटना

बिहार में रफ्तार का कहर जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सुपौल जिले से आ रही है, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गयी है। वही दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गये हैं। इस दौरान मौके पर अफरा-तफरी मच गयी। घटना किशनपुर थाना क्षेत्र के नेमनमा चौक के पास की है। जहां दो बाइकों की सीधी भीड़ंत में यह हादसा हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर तीनों बाइक सवार की मौत हो गयी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों बाइक तेज रफ्तार में थीं और अचानक आमने-सामने आ जाने के बाद अफरा-तफरी मच गयी। वहीं तीन अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल सुपौल सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान एक और युवक की मौत हो गई। इस तरह हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है। सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि दो घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें बेहतर ईलाज के लिए रेफर करने की तैयारी की जा रही है। घायल युवकों का इलाज जारी है और डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। बताया जा रहा है कि एक बाइक पर तीन युवक सवार थे। सभी युवक 18 से 25 वर्ष उम्र के बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक मृतकों और घायलों की आधिकारिक पहचान नहीं हो पाई है। हादसे के पीछे ओवरस्पीडिंग और लापरवाही की आशंका जताई जा रही है, लेकिन दुर्घटना के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है। घटना की सूचना मिलते ही किशनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुर्घटनाग्रस्त दोनों बाइकों को जब्त कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की गहन जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

निगरानी की बड़ी कार्रवाई, 12 हजार घूस लेते पंचायत तकनीकी सहायक गिरफ्तार

एजेंसी। पटना

भ्रष्टाचारियों के खिलाफ निगरानी विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर मधुबनी में बड़ी कार्रवाई हुई है। निगरानी विभाग की टीम ने कलुआही प्रखंड में 12 हजार रुपये की घूस लेते हुए पंचायत तकनीकी सहायक को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।मिली जानकारी के अनुसार, कलुआही प्रखंड के पंचायती राज विभाग में काम कर रहे तकनीकी सहायक हरि रंजन कुमार के खिलाफ रिश्वत लेने की शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद निगरानी विभाग ने जाल बिछाया। पटना से आई नौ सदस्यीय टीम ने डीएसपी मो. वसीम फिरोज के नेतृत्व में यह कार्रवाई की।टीम ने पहले से योजना बनाई और जैसे ही आरोपी ने 12 हजार रुपये की घूस ली, उसी समय निगरानी की टीम ने उसे पकड़ लिया। निगरानी डीएसपी मो. वसीम फिरोज ने बताया कि पंचायत तकनीकी सहायक 12 हजार रुपये की घूस मांग रहा था। पटना से आई नौ सदस्यीय टीम ने उसे घूस के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल टीम उससे पूछताछ कर रही है।गिरफ्तारी के बाद आरोपी को जरूरी पूछताछ के लिए टीम अपने साथ ले गई। इस कार्रवाई के बाद मधुबनी जिले में, खासकर कलुआही प्रखंड कार्यालय में, हड़कंप मच गया है। मामले में आगे की जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि निगरानी विभाग मधुबनी में लगातार छापेमारी कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में कई अधिकारी निगरानी के हत्थे चढ़ चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग पूरी तरह भ्रष्टाचार से बाज नहीं आ रहे हैं।

पटना में कोचिंग की छत से गिरकर छात्रा की मौत, सीसीटीवी में पीछे दिखे दो युवक, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

एजेंसी। पटना

नीट छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अभी सुलझा भी नहीं था की एक और मामला पटना में सामने आ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर पटना के फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र से सामने आ रही है, जहां कोचिंग की छत से 12वी की एक छात्रा के गिरने से मौत हो गयी। इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गयी। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू की। घटना पटना एम्स गोलंबर के पास स्थित हरी नगर कॉलोनी की है। जहां कोचिंग में यह घटना हुई। लड़की के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या की गयी है। फिलहाल पुलिस घटना की सभी बिन्दुओं की जांच कर रह ही। कोचिंग में लगे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगालने में लगी है। सीसीटीवी फुटेज में छात्रा सीढियों से जाते दिख रही है। उसके पीछे दो लड़के भी नजर आ रहे हैं। जिसके कारण परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। पुलिस ने कोचिंग के स्टाफ और आस-पास के लोगों से पूछताछ की। पता चला कि जहां पर

यह कोचिंग जहां स्थित है वहां आम लोगों की आवाजाही नहीं है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है। वही पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। मामला हत्या है या फिर आत्महत्या यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। छात्रा की पहचान फुलवारीशरीफ निवासी 17 वषीर्या पिंकी कुमारी के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि बेटी सुबह 8 बजे कोचिंग के लिए निकली थी। एक घंटा बाद पता चला कि उसकी मौत हो गयी। परिजनों का आरोप है कि रेप के बाद बेटी की हत्या की गयी है। उसे कोचिंग के चौथे तल्ले से धक्का देकर हत्या की गयी है। सूचना मिलने के बाद जब वो कोचिंग पहुंचे तो देखा कि पिंकी की लाश सड़क पर लाश पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। उसका चप्पल भी वही मिला है। परिजन रेप के बाद हत्या किये जाने की बात कर रहे हैं और पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

बिहार में ठंड पड़ी कमजोर : न्यूनतम तापमान बढ़ा, उत्तर बिहार में सुबह घने कोहरे की संभावना

एजेंसी। पटना

पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिहार में ठंड का असर अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगा है। राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे सुबह और रात की ठिठुरन में कमी महसूस की जा रही है। दिन के समय धूप निकलने से लोगों को राहत मिल रही है और मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। खासकर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, दरभंगा और पूर्वी चंपारण जैसे जिलों में दृश्यता कम हो सकती है। ऐसे में सुबह-सवेरे यात्रा करने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी

गई है। वहीं, पटना सहित दक्षिण और मध्य बिहार के अधिकांश हिस्सों में मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई गई है। न्यूनतम तापमान में हो रही बढ़ोतरी से किसानों और आम लोगों दोनों को राहत मिली है। बीते कुछ दिनों तक पछुआ हवाओं के कारण ठंड का असर ज्यादा था, लेकिन अब हवा की दिशा में बदलाव और धूप की तीव्रता बढ़ने से मौसम में नरमी आ गई है। अधिकतम तापमान भी सामान्य से थोड़ा ऊपर दर्ज किया जा रहा है, जिससे दिन में हल्की गर्मी का अहसास हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, फिलहाल किसी बड़े पश्चिमी विक्षोभ या मौसम प्रणाली के सक्रिय होने की संभावना नहीं है। यही वजह है कि राज्य में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क और स्थिर बने रहने की उम्मीद है। हालांकि, सुबह के समय कोहरे और हल्के कुहासे के कारण सड़क और रेल यातायात पर कुछ असर पड़ सकता है। पटना शहर में सुबह हल्की ठंड और दिन में तेज धूप का असर देखने को मिल रहा है। शहरवासियों का कहना है कि अब स्वेटर और जैकेट की जरूरत कम होती जा रही है। वहीं, ग्रामीण इलाकों में भी लोग सुबह-शाम हल्की ठंड के बावजूद दिन में खुले कपड़ों में नजर आ रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम में यह बदलाव रबी फसलों के लिए अनुकूल साबित हो सकता है। गेहूं, सरसों और चना जैसी फसलों को पर्याप्त धूप मिलने से उनकी बढ़वार बेहतर होगी। हालांकि, सुबह के कोहरे से सब्जी और दलहन फसलों पर नमी का असर पड़ सकता है, इसलिए किसानों को फसलों की निगरानी करने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों को बदलते मौसम के अनुसार सतर्क रहने की अपील की है। सुबह और रात के समय हल्की ठंड बनी रह सकती है, इसलिए बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। साथ ही, कोहरे के दौरान वाहन चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है।कुल मिलाकर, बिहार में ठंड अब धीरे-धीरे विदा ले रही है और मौसम वसंत की ओर बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी के संकेत हैं, जिससे लोगों को सर्दी से राहत तो मिलेगी, लेकिन दिन के समय गर्मी का एहसास भी बढ़ सकता है।

डिब्रूगढ़-अमृतसर एक्सप्रेस में 40 लाख का पोस्ता दाना बरामद, जांच तेज

एजेंसी। पटना

रेल पुलिस ने हाजीपुर स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए डिब्रूगढ़-अमृतसर एक्सप्रेस से 1869 किलोग्राम विदेशी पोस्ता दाना बरामद किया है। जब्त माल की अनुमानित कीमत स्थानीय बाजार में करीब 40 लाख 94 हजार रुपये आंकी गई है।वरीय अधिकारियों के निर्देश पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) हाजीपुर ने सीआईबी सोनपुर और मुजफ्फरपुर कस्टम विभाग के साथ संयुक्त अभियान चलाया। कस्टम विभाग से मिली गुप्त सूचना के आधार पर 15933 अप डिब्रूगढ़-अमृतसर एक्सप्रेस की हाजीपुर स्टेशन पर तलाशी ली गई।ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पहुंचते ही पार्सल बोगी को वाणिज्य विभाग हाजीपुर के सीसी राजीव रंजन चौधरी और वर्किंग ट्रेन मैनेजर वीरेंद्र कुमार (मुख्यालय बरौनी) की मौजूदगी में खोला गया। जांच के दौरान दीमापुर से मुरादाबाद के लिए बुक किए गए कई बिल्टी नंबरों के तहत लगभग 30 बोरे में कुल 1869 किलो विदेशी पोस्ता दाना बरामद हुआ। पूरी कार्रवाई आरपीएफ थाना अध्यक्ष साकेत कुमार के नेतृत्व में की गई। टीम में कस्टम अधीक्षक सुदामा कुमार, निरीक्षक अनूप कुमार तथा आरपीएफ के नर्सिंग यादव, चंद्रशेखर कुमार और पवन कुमार शामिल थे। जब्त पोस्ता दाना की कीमत 2300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लगभग 40.94 लाख रुपये आंकी गई है।